@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

हमें जनसेवा की साधना करते रहनी है: जगत प्रकाश नड्डा

वर्ष-16, अंक-11 16-30 जून, 2021 (पाक्षिक) ₹20

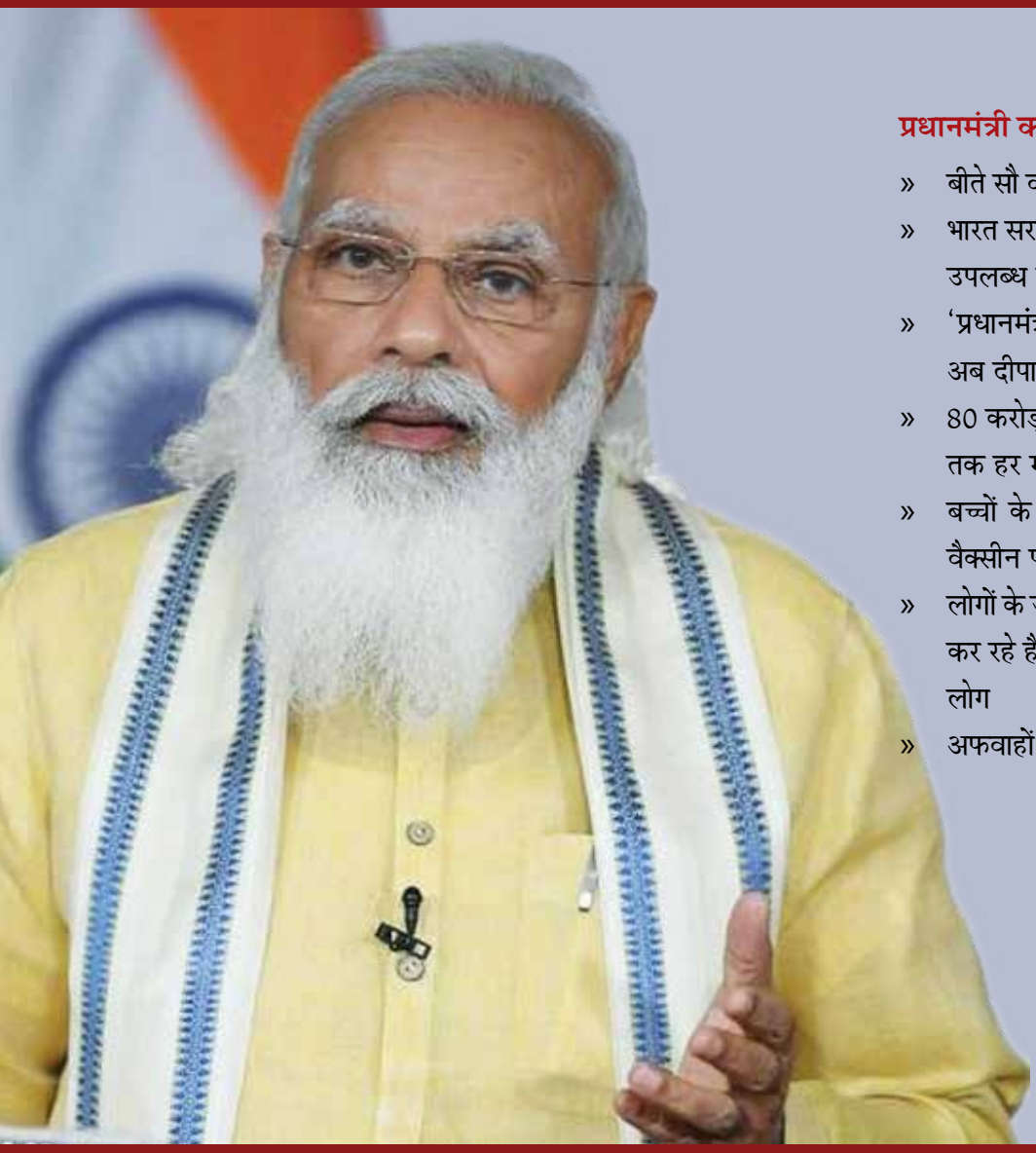

प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन

- बीते सौ वर्षों में कोरोना सबसे बड़ी महामारी
- भारत सरकार ही सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी
- 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' अब दीपावली तक
- 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज
- बच्चों के वैक्सीन पर ट्रायल और 'नेज़ल' वैक्सीन पर रिसर्च
- लोगों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वाले लोग
- अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत

सभी के लिए निःशुल्क वैक्सीन: प्रधानमंत्री

मोदी सरकार 2.0 के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'सेवा ही संगठन' कार्यक्रम को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

श्री गोपीनाथ मुंडेजी की स्मृति में उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर नई दिल्ली में भारतीय डाक विभाग के लिए विशेष आवरण का विमोचन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ दो ऑक्सीजन संयंत्रों की नींव रखी और हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री को झंडी दिखाकर रवाना किया

नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 'सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली-कंसल्टेशन (सेहत) ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सेवारत सशस्त्र कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करता है

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रयासों से वर्धा में जेनेटेक लाइफ साइंसेज ने कोविड के बाद तेजी से फैल रहे काले फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी इमल्शन इंजेक्शन तैयार किया है। अब तक भारत में केवल एक ही कंपनी इसका उत्पादन करती थी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होगा निःशुल्क टीका: नरेन्द्र मोदी**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जून को राष्ट्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस महामारी को पिछले सौ वर्षों में सबसे बड़ी आपदा बताते हुए...

10 **प्रधानमंत्री ने भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए चार...

11 **डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक में क्रांति लाएगा 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन'**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन...

12 **हमें जनसेवा की साधना करते रहनी है : जगत प्रकाश नड्डा**

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 2.0 के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन...

30 **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने की 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' की सराहना**

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत की ओर से 11 जून को जारी एक...

वैचारिकी

हमारे राष्ट्रवाद का आधार सांस्कृतिक है / **दीनदयाल उपाध्याय** 22

श्रद्धांजलि

महान शिक्षाविद, प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी 24

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का निधन 25

मन की बात

पिछले सात वर्षों में देश ने राष्ट्रीय गौरव के कई क्षणों का किया अनुभवः नरेन्द्र मोदी

अन्य

'हम बच्चों में एक उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं' 08

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 'सेवा ही संगठन 2.0' अभियान 15

नवंबर, 2021 तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने मिलता रहेगा मुफ्त खाद्यान्न 17

अब भारतीय रेल होगी और सुरक्षित 19

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत की 25

पूरी दुनिया के लिए जाना चाहिए 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' का संदेशः नरेन्द्र मोदी 26

खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र के केन्द्र में हैः नरेन्द्र मोदी 29

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा।

जगत प्रकाश नड्डा

कोरोना की लड़ाई में दुनिया में और भारत में फर्क है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां ये लड़ाई सिर्फ सरकार ने नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने 130 करोड़ जनता को प्रेरित करके तैयार किया और समाज ने अलग-अलग तरीके से इस लड़ाई में योगदान दिया।

अमित शाह

जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रति मोदी सरकार ने सदैव संकल्पबद्ध होकर कार्य किया है। इसी क्रम में आज देशभर में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीका उपलब्ध कराने के ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं।

राजनाथ सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के सात वर्ष पूरे हुए हैं। इन सात वर्षों में जनसेवा, लोक कल्याण, विकास, सुशासन एवं सुधार का नया अध्याय लिखा गया है। गरीब से गरीब व्यक्ति के भी सशक्तिकरण का प्रयास प्रधानमंत्रीजी के मार्गदर्शन में हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करने के लिए प्रधानमंत्रीजी को अत्यंत साधुवाद।

बी.एल. संतोष

पश्चिम बंगाल में राज्य प्रायोजित हिंसा आनेवाले समय में भारत के संवैधानिक लोकाचार पर एक शर्मनाक धब्बा बनने जा रही है। पश्चिम बंगाल में अत्याचारों के खिलाफ 100 से अधिक दलित और आदिवासी प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

थावरचंद गहलोत

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा।

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
गंगा दशहरा (20 जून)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा 18-44 आयुवर्ग के लोगों के लिए भी निःशुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा से पूरा देश आश्वस्त है कि अब हर किसी को आसानी से टीका उपलब्ध होगा। ध्यान देने योग्य है कि मोदी सरकार पहले से ही 45 वर्ष से ऊपर के आयु वाले लोगों के लिये निःशुल्क टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चला रही है। पूर्व में कुछ राज्यों द्वारा भी टीके की मांग को देखते हुए 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण कार्य को विकेन्द्रित किया गया था। जब कुछ राज्य प्रभावी ढंग से इस अभियान को नहीं चला पा रहे थे एवं टीका प्राप्त करने में अपनी असमर्थता जता रहे थे, ऐसे में कोविड–19 महामारी के विरुद्ध चल रहे युद्ध की गति धीमी पड़ने की आशंका उत्पन्न होने लगी थी।

एक ओर जहां भाजपा शासित राज्य निःशुल्क टीकाकरण की घोषणा कर चुके थे, वहीं कई अन्य राज्य टीके की उपलब्धता के लिए केन्द्र पर निर्भर रहे। इससे उत्पन्न आशंकाओं एवं संशय को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अब 45+ आयु वर्ग के साथ–साथ 18-44 आयु वर्ग के लिये भी केन्द्र द्वारा निःशुल्क टीकाकरण का दायित्व अब अपने ऊपर ले लिया है। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि निकट भविष्य में देश कोविड–19 महामारी को निर्णायक रूप से नियंत्रित करने में सफल होगा।

राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों के लिए 'गरीब कल्याण योजना' के नवम्बर माह तक विस्तार करने की भी घोषणा की है। इस योजना से 80 करोड़ लोगों को न केवल खाद्य सुरक्षा मिली है बल्कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी विभिन्न 'लॉकडाउन' में बिना किसी भय एवं आशंका के कोविड–19 महामारी के विरुद्ध युद्ध में जुड़ सका है। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल एवं अन्य आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत ही सफल कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इससे इस वैश्विक महामारी के दौर में गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भारी राहत पहुंची है। महामारी के दूसरे दौर में इसके विस्तार से जन–जन में यह विश्वास और भी अधिक सुदृढ़ हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने में देश सक्षम है और महामारी पर विजय के लिए कृतसंकल्पित है।

आज जब निःशुल्क टीकाकरण अभियान की गति तेज हो रही है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि भारत कोविड–19 महामारी पर निकट भविष्य में निर्णायक विजय प्राप्त करेगा

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'पीएम–केयर्स' के अंतर्गत, जिन बच्चों ने कोविड–19 के कारण अपने माता–पिता को खो दिया है, उनके लिए अनेक राहतों की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों की शिक्षा के साथ–साथ उसके 18 वर्ष होने पर 10 लाख रुपये के 'कॉर्पस फंड' की भी व्यवस्था की गई है। इन बच्चों के लिए उच्चतम शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। इसके साथ ही, मोदी सरकार ने कोविड–19 के कारण जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, उनके लिये भी कई सहायता की घोषणाए की गई हैं। इस वैश्विक महामारी में विश्वभर में अनेक परिवारों ने भयानक त्रासदियों को सहा है तथा भारत में कई लोगों ने जानें गंवाई हैं और उन पर निर्भर परिवार अब एक अनिश्चित भविष्य से जूझ रहे हैं। जहां पूरा देश इन परिवारों के साथ एकजुट खड़ा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार इनके लिए अनेक सहायता एवं राहत के कार्यक्रम घोषित कर विपरीत परिस्थितियों में इनका संबल बनी है।

एक ओर जहां विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र गति से चलने वाला टीकाकरण अभियान दिनोंदिन और अधिक गतिमान हो रहा है, पूरा राष्ट्र अपने वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं पर गौरवान्वित है। आज देश में एक नहीं बल्कि दो कोविड टीकों का निर्माण हुआ है और कई अन्य टीके निर्माण की प्रक्रिया में हैं। साथ ही, बच्चों के लिए भी टीके परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं जो कोविड–19 महामारी के विरुद्ध एक और मील के पत्थर साबित होंगे। भारत अपने चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्साकर्मियों, लैब टेक्नीशियनों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं कोरोना योद्धाओं पर भी गर्व का अनुभव कर रहा है, जिन्होंने महामारी के इस दौर में निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा की है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के दिशा–निर्देशों में 'सेवा ही संगठन–2.0' कार्यक्रम के अंतर्गत करोड़ों भाजपा कार्यकताओं ने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री बांटी है तथा कोरोना पीड़ितों की सेवा का कार्य किया है। आज जब निःशुल्क टीकाकरण अभियान की गति तेज हो रही है, इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि भारत कोविड–19 महामारी पर निकट भविष्य में निर्णायक विजय प्राप्त करेगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

प्रधानमंत्री का राष्ट्र संबोधन

18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध होगा निःशुल्क टीका: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जून को राष्ट्र को संबोधित किया। श्री मोदी ने कोरोना महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस महामारी को पिछले सौ वर्षों में सबसे बड़ी आपदा बताते हुए उन्होंने इसे एक ऐसी महामारी के रूप में चिन्हित किया जिसे आधुनिक दुनिया में न तो देखा गया और न ही अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस महामारी से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। श्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं।

टीकाकरण की रणनीति पर पुनर्विचार करने और 1 मई से पहले की व्यवस्था को वापस लाने की कई राज्यों की मांग को देखते हुए श्री मोदी ने घोषणा की कि राज्यों के जिम्मे जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब भारत सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को दो सप्ताह में अमल में ला दिया जाएगा। दो सप्ताह में केन्द्र और राज्य नए दिशानिर्देशों के मुताबिक जरूरी तैयारियां करेंगे।

भारत सरकार टीके के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा

उन्होंने आगे घोषणा की कि आगामी 21 जून से भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीका प्रदान करेगी। भारत सरकार टीके के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक करोड़ों लोगों

को मुफ्त टीका मिल चुका है, अब इसमें 18 वर्ष वाले आयु-वर्ग को जोड़ा जाएगा।

श्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि भारत सरकार सभी नागरिकों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों द्वारा 25 प्रतिशत टीकों की सीधी खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। राज्य सरकारें इस बात की निगरानी करेंगी कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों की निर्धारित कीमत पर केवल 150 रुपये का सर्विस चार्ज लिया जाए।

दीपावली तक 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना'

एक अन्य बड़ी घोषणा के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने के निर्णय से अवगत कराया। यानी नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने निर्धारित मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान सरकार गरीबों के साथ उनकी सभी जरूरतों के लिए उनके दोस्त के रूप में खड़ी है।

अप्रैल और मई के महीनों के दौरान इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के सभी तंत्र को तैनात करके इस चुनौती से युद्धस्तर पर निपटा गया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी मांग पहले कभी नहीं महसूस की गई थी।

उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर टीके बनाने वाली कंपनियां और देश टीकों की वैश्विक मांग की तुलना में काफी पीछे हैं। ऐसी परिस्थिति में मेड इन इंडिया टीका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। श्री मोदी ने कहा कि अतीत में विदेशों में विकसित होने के दशकों बाद भारत को टीके मिलते थे। अतीत में इसका नतीजा हमेशा एक ऐसी स्थिति के रूप में होता था जिसमें भारत में टीकाकरण जहां शुरू भी नहीं होता था, वहीं अन्य देश टीकाकरण का काम खत्म कर चुके होते थे।

श्री मोदी ने कहा कि हमने मिशन मोड में काम करते हुए 5-6 वर्षों में टीकाकरण कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने न सिर्फ टीकाकरण की गति बढ़ाई, बल्कि उसका दायरा भी बढ़ाया।

श्री मोदी ने कहा कि इस बार भारत ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया और साफ इरादों, स्पष्ट नीति और निरंतर कड़ी मेहनत के जरिए भारत में कोविड के लिए न केवल एक, बल्कि भारत में निर्मित दो टीके लॉन्च किए गए। हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता साबित की। देश में अब तक टीके की 23 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं।

उन्होंने याद किया कि वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन उस समय किया गया था जब कोविड-19 के केवल कुछ हजार मामले ही थे और टीका बनाने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण में हर संभव तरीके से सहयोग दिया गया।

तीन और टीकों का परीक्षण अग्रिम चरण में

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ने वाली है। उन्होंने बताया कि आज सात कंपनियां अलग-अलग तरह के टीके तैयार कर रही हैं। श्री मोदी ने जानकारी दी कि तीन और टीकों का परीक्षण अग्रिम चरण में है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए दो टीकों और एक 'नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके' के परीक्षण के बारे में भी बताया।

श्री मोदी ने कहा कि हमने मिशन मोड में काम करते हुए 5-6 वर्षों में टीकाकरण कवरेज को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया है

श्री मोदी ने टीकाकरण अभियान के बारे में विभिन्न हलकों की ओर से आने वाले अलग-अलग विचारों पर प्रकाश डाला। ज्योंहि कोरोना के मामले घटने लगे, राज्यों के लिए विकल्प की कमी को लेकर सवाल उठने लगे और कुछ लोगों ने सवाल किया कि केन्द्र सरकार सब कुछ क्यों तय कर रही है। लॉकडाउन में लचीलापन और 'सभी पर एक ही तरह की बात लागू नहीं होती' के तर्क को आगे बढ़ाया गया।

श्री मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से अप्रैल के अंत तक भारत का टीकाकरण कार्यक्रम ज्यादातर केन्द्र सरकार के अधीन चलाया गया। सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण का काम आगे बढ़ रहा था और लोग अपनी बारी आने पर टीकाकरण कराने में अनुशासन दिखा रहे थे। इन सबके बीच टीकाकरण के विकेंद्रीकरण की मांग उठाई गई और कुछ आयु वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देने के निर्णय की बात उठाई गई। कई तरह के दबाव डाले गए और मीडिया के कुछ हिस्से ने इसे अभियान के रूप में चलाया।

उन्होंने टीकाकरण के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के बारे में आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्व लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं और इनके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है। ■

'हम बच्चों में एक उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 मई को कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की सहायता करने के लिए उठाये जा सकने वाले कदमों के बारे में चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने वर्तमान कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की।

इन उपायों की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश बच्चों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेगा ताकि वे मजबूत नागरिक के रूप में उभरें और उनका भविष्य उज्ज्वल हो।

श्री मोदी ने कहा कि ऐसे कठिन समय में एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उनमें एक उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं। कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या माता-पिता में से जीवित बचे या कानूनी अभिभावक/दत्तक माता-पिता को खोने वाले सभी बच्चों को 'पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन' योजना के तहत सहायता दी जाएगी।

मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा

बच्चे के नाम पर सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट)

पीएम केयर्स 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये का कोष बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक योजना के माध्यम से योगदान देगा। यह कोषः

क- 18 वर्ष की आयु से अगले पांच वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता/छात्रवृति देने के लिए उपयोग किया जाएगा, और

ख- 23 वर्ष की आयु पूरी करने पर उसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एकमुश्त के रूप से कोष की राशि मिलेगी।

स्कूली शिक्षा: 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए

- बच्चे को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
- अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी।
- पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।

स्कूली शिक्षा: 11-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए

- बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय जैसेकि सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय आदि में प्रवेश दिलाया जाएगा।
- यदि बच्चे को अभिभावक/दादा-दादी/विस्तारित परिवार की देखरेख में रखा जाना है, तो उसे निकटतम केन्द्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश दिलाया जाएगा।
- अगर बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स से आरटीई के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी।
- पीएम केयर्स वर्दी, पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक पर होने वाले खर्च का भी भुगतान करेगा।

उच्च शिक्षा के लिए सहायता

मौजूदा शिक्षा ऋण के मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण दिलाने में बच्चे की सहायता की जाएगी। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा। विकल्प के रूप में ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत स्नातक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क/पाठ्यक्रम शुल्क के बराबर की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो बच्चे मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स एक समकक्ष छात्रवृत्ति प्रदान करेगा।

कोविड से मृतक के आश्रितों को दी जाएगी पारिवारिक पेंशन

कोविड से मृतक के आश्रितों को दी जाएगी पारिवारिक पेंशन

'बच्चों के लिए पीएम केयर्स- कोविड प्रभावित बच्चों का सशक्तिकरण' के तहत घोषित उपायों के अलावा भारत सरकार ने उन परिवारों की मदद करने के लिए 29 मई को कई और उपायों की घोषणा की, जिन्होंने कोविड के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। इन उपायों के तहत कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पेंशन दी जाएगी और इसके साथ ही बढ़ा हुआ एवं उदार बीमा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इन सभी परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि इन योजनाओं के जरिए इन परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत पारिवारिक पेंशन

» इन परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने और अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद करने हेतु रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के लिए ईएसआईसी पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है।

» इन व्यक्तियों के आश्रित परिवारिक सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90% के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। यह लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से 24 मार्च, 2020 से और इस तरह के सभी मामलों के लिए 24 मार्च, 2022 तक उपलब्ध होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना (ईडीएलआई)

» ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ-साथ उदार बना दिया गया है। अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा यह योजना विशेषकर उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगी जिन्होंने कोविड के कारण अपनी जान गंवा दी है।

» अधिकतम बीमा लाभ की राशि 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है।

» 2.5 लाख रुपये के न्यूनतम बीमा लाभ के प्रावधान को बहाल कर दिया गया है और यह पूर्वव्यापी प्रभाव से 15 फरवरी, 2020 से अगले तीन वर्षों के लिए लागू होगा।

» ठेके पर काम करने वाले/आकस्मिक कामगारों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केवल एक ही प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार करने की शर्त को उदार बना दिया गया है, अब इसका लाभ यहां तक कि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में अपनी नौकरी संभवतः बदल दी थी। ■

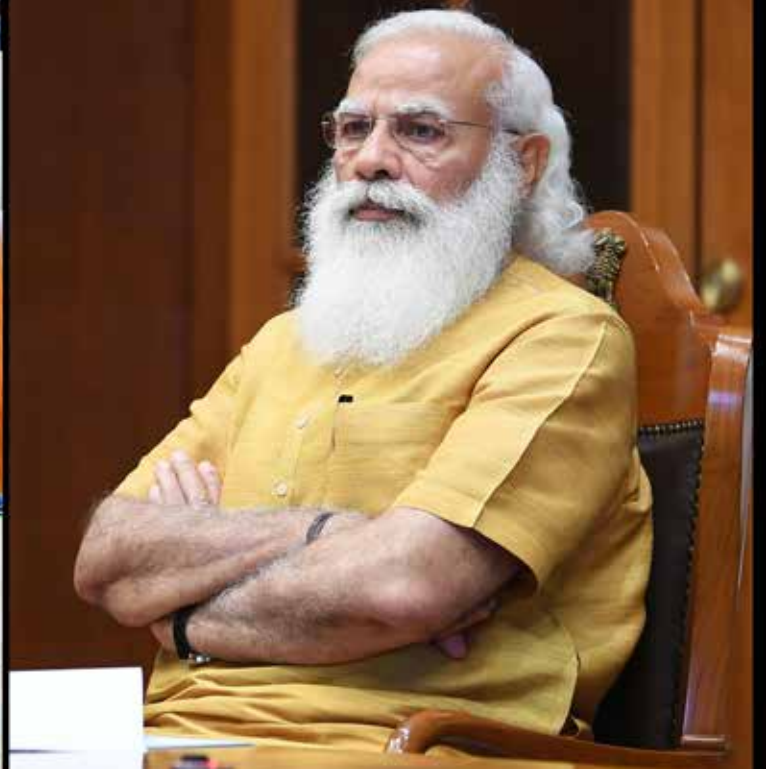

प्रधानमंत्री ने भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए चार जून को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं पर अपनी विस्तृत प्रस्तुति दी।

श्री मोदी को टीकों की वर्तमान उपलब्धता और इसे बढ़ाने की योजना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें विभिन्न वैक्सीन निर्माताओं को टीकों के उत्पादन में तेजी लाने में मदद करने के लिए किए गए प्रयासों से भी अवगत कराया गया। भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है और अधिक उत्पादन इकाइयों की सुविधा, कच्चे माल के वित्तपोषण और आपूर्ति के मामले में उन्हें सहायता प्रदान कर रही है।

भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं को अधिक उत्पादन इकाइयों की सुविधा, कच्चे माल के वित्तपोषण और आपूर्ति के मामले में मदद कर रही है

श्री मोदी ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के साथ-साथ अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में टीकाकरण कवरेज की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु के साथ-साथ 18-44 आयु वर्ग में भी टीकाकरण कवरेज का जायजा लिया।

श्री मोदी ने विभिन्न राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वैक्सीन की बर्बादी की संख्या अभी भी अधिक है इसे कम किए जाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

अधिकारियों ने टीकाकरण की प्रक्रिया को लोगों के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए तकनीकी मोर्चे पर किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी।

अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को टीके की उपलब्धता पर राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही अग्रिम जानकारी के बारे में बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि राज्यों को यह जानकारी जिला स्तर पर देने को कहा गया है ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो।

बैठक में रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों ने भाग लिया। ■

डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक में क्रांति लाएगा 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) की समीक्षा के लिए 27 मई को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान एनडीएचएम के शुभारंभ की घोषणा की थी। उसके बाद से कई डिजिटल मॉड्यूल एवं रजिस्ट्रियां विकसित की गई हैं और इस मिशन को छह केन्द्रशासित प्रदेशों में शुरू किया गया है।

अब तक लगभग 11.9 लाख स्वास्थ्य पहचान-पत्र (आईडी) बनाये जा चुके हैं और 3106 डॉक्टरों एवं 1490 स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सुविधाओं ने इस प्लेटफार्म पर पंजीकरण कराया है। इस बात की परिकल्पना की गई है कि डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित एक खुले और इंटरऑपरेबल आईटी नेटवर्क-यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई) को जल्द ही शुरू किया जाना चाहिए।

एनडीएचएम बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा

यह इंटरफ़ेस सार्वजनिक और निजी समाधानों एवं एप्प को काम करने और उसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बनने में सक्षम बनायेगा। यह उपयोगकर्ताओं को टेली-परामर्श या प्रयोगशाला जांच जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को खोजने, उन्हें बुक करने और उनका लाभ उठाने की अनुमति देगा।

यह प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि केवल सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही इस इकोसिस्टम में शामिल हों। इसके द्वारा नवाचारों और विभिन्न सेवाओं के जरिए नागरिकों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक क्रांति लाये जाने की संभावना है। इस प्रकार पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों का और भी अधिक कारगर तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

बैठक में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित यूपीआई ई-वाउचर की अवधारणा पर भी चर्चा की गई। डिजिटल भुगतान का यह विकल्प विशिष्ट उद्देश्य से जुड़े वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनायेगा जिसका उपयोग केवल इच्छुक उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित और कुशल वितरण के लिए उपयोगी हो सकता है और यूपीआई ई-वाउचर का तत्काल उपयोग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो सकता है।

श्री मोदी ने निर्देश दिया कि एनडीएचएम के तहत गतिविधियों में विस्तार करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि एनडीएचएम बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि तकनीकी प्लेटफार्म और रजिस्ट्रियों का निर्माण भले ही अनिवार्य आवश्यक तत्व हैं, लेकिन नागरिकों के लिए इस प्लेटफार्म की उपयोगिता एक डॉक्टर के साथ टेली परामर्श, एक जांच प्रयोगशाला की सेवाओं, जांच रिपोर्ट या स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से डॉक्टर को स्थानांतरित करने और उपरोक्त किसी भी सेवा के लिए डिजिटल रूप से भुगतान करने जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में देशभर के नागरिकों को सक्षम बनाने के जरिए ही दिखाई देगी। ■

हमें जनसेवा की साधना करते रहनी है: जगत प्रकाश नड्डा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार 2.0 के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन 2.0 के तहत देश भर में आहूत पार्टी के विशेष सेवा अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा 30 मई, 2021 को दिल्ली की गीता कॉलोनी के सफेदा बस्ती से वर्चुअली जुड़े। इस अवसर पर उन्होंने सफेदा बस्ती के लोगों से संवाद भी किया। श्री नड्डा ने सफेदा बस्ती के दिव्यांग बंधु श्री अमन जी से भी बात की और लोगों की मदद के उनके जज्बे को सराहा। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता, स्थानीय भाजपा सांसद श्री गौतम गंभीर एवं शहादरा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा भी उपस्थित थे। पूरा कार्यक्रम कोविड के सख्त प्रोटोकॉल के तहत किया गया। श्री नड्डा ने दिल्ली प्रदेश भाजपा की टीम, सांसद श्री गौतम गंभीर के प्रयासों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की दिल से सराहना की।

सफेदा गांव में सेवा ही संगठन अभियान को वर्चुअली संबोधित करने के बाद श्री नड्डा ने दिल्ली के सांसद श्री प्रवेश वर्मा के सहयोग से दिल्ली के लिए राहत सामग्रियों से भरे ट्रकों को भी रवाना किया। इन राहत सामग्रियों में 5,000 राशन किट्स, एक लाख 5-लेयर एन-95 मास्क, 4 लाख फेस शील्ड और 5000 ऑक्सीजन कैनुला शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता की सेवा हेतु कटिबद्ध होकर काम करने के लिए पार्टी सांसद श्री प्रवेश वर्मा को साधुवाद दिया और उनके प्रयासों की सराहना की।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के 7 वर्ष और दूसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने विगत 7 सालों में देश को जो मजबूती प्रदान की है और दुनिया में देश को स्थापित करते हुए विकास के रास्ते पर अग्रसर किया है, वह उल्लेखनीय है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को लंबी उम्र मिले और वे लंबे समय तक इसी तरह राष्ट्र की सेवा करते रहें। श्री नरेन्द्र मोदी 'आत्मनिर्भर भारत' का जो लक्ष्य लेकर चले हैं, उसे हम सब मिलकर साकार करेंगे।

उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण और इससे उत्पन्न हालात के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस दिन को एक संकल्प के तौर पर सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान समय में लोगों को मदद की आवश्यकता है, उसे देखते हुए सेवा ही संगठन 2.0 अभियान के तहत आज पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता देश के एक लाख से अधिक गांवों में जरूरतमंदों की सेवा करते हुए हर मुसीबत को सुलझाने में प्रयासरत है। मैं सेवा कार्य में जी-जान से लगे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। इस सेवा अभियान के तहत जरूरतमंदों में राहत सामग्री, राशन किट, दवाइयां, फेस मास्क, सेनिटाइजर इत्यादि वितरित किये जा रहे हैं। साथ ही, पार्टी कार्यकर्ता टेस्टिंग और ऑक्सीजन की आपूर्ति इत्यादि में भी मदद कर रहे हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि बीते तीन दिनों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स आयोजित किये हैं और 50,000 ब्लड यूनिट्स डोनेट करने का लक्ष्य तय किया है, हम इसे पूरा करेंगे। पार्टी के सभी सांसद, विधायक और केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रियों ने आज के दिन तय किया है कि

वे कोविड प्रोटोकॉल के सभी नियमों को पूरा करते हुए कम से कम दो गांवों में जायेंगे और राहत अभियान चलाएंगे। मैं भी इस अभियान में भाग ले रहा हूं और लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर वर्चुअली सफेदा गांव के इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं। हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से लोगों को इस संकट की घड़ी में काफी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे हुए हैं, वहीं दूसरे राजनीतिक दल या तो क्वारंटाइन हो गए हैं या लॉकडाउन हो गए हैं, जनता के लिए तो वे कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इन पार्टियों के नेता या तो रैलियों या प्रेस कांफ्रेंस में दिखाई देते हैं या फिर ट्विटर पर।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों तक मुफ्त खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था की। इस बार भी कोरोना संक्रमण बढ़ने पर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दो महीनों के लिए लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंचाए जा रहे हैं। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि यह योजना अमेरिका, कनाडा और पूरे यूरोप की जनसंख्या से भी अधिक लोगों तक हम पहुंचा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आठवीं क़िस्त दी है। अब तक किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के अकाउंट में लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए 3,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था भी की गई है।

उन्होंने कहा कि विगत एक वर्ष में कोरोना के दौरान इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल-चूल सुधार हुआ है। पहले जहां हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी महज 1500 प्रतिदिन की थी, वहीं यह आंकड़ा अब बढ़कर 25 लाख प्रतिदिन हो गया है। इसी तरह, पहले कोरोना टेस्टिंग के लिए महज एक ही लैब था, आज देश में 2500 टेस्टिंग लैब्स हैं। देश में आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़कर 14 लाख और आईसीयू बेड्स की संख्या भी बढ़कर 81,000 हो गई है। भारत पीपीई किट्स, फेस मास्क, सेनिटाइजर्स, वेंटीलेटर्स इत्यादि के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका है। यह सब मोदी सरकार के अथक परिश्रम के कारण संभव हो पाया है।

वैक्सीन पर चर्चा करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि जब मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कमर कसी और वैज्ञानिकों एवं लैब्स को प्रेरित किया तो उस वक्त इस मुहिम का भरपूर मजाक उड़ाया गया। इतना ही नहीं, जब वैक्सीन बन गई और इसके इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दी गई तो कुछ विपक्षी पार्टियों और उसके नेताओं ने वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए देश को बदनाम करने का अभियान चलाया। आज वही लोग वैक्सीन-वैक्सीन चिल्ला रहे हैं, वैक्सीन पर हल्ला मचा

रहे हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई नई वैक्सीन बनती है तो उसके रॉल-आउट होने में लगभग 9 से 12 महीने लगते हैं लेकिन हमने महज 130 दिनों में 20 करोड़ से अधिक डोज एडमिनिस्टर कर दिखाया है। शुरुआत में सीरम इंस्टीटयूट कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन बना रही थी लेकिन आज भारत में 13 कंपनियां मिलकर इन वैक्सीन को बना रही है। स्पूतनिक का भी भारत में उत्पादन हो रहा है। भारत बायोटेक की क्षमता अभी लगभग एक करोड़ डोज के उत्पादन की है जबकि अक्टूबर तक या क्षमता बढ़कर 10 करोड़ प्रतिमाह हो गई है। इस वर्ष के अंत तक देश में सब लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो जायेगी।

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी पड़ने पर हमारी सरकार के अथक प्रयासों से ऑक्सीजन उत्पादन कई गुना बढ़ गया और एक सप्ताह में ही ऑक्सीजन की हर जगह अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई। देश भर में लगभग 1,500 नए ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं। एमसीडी का कोई हॉस्पिटल बिना ऑक्सीजन प्लांट के न रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन प्लांट लगे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस में कारगर दवाइयों के निर्माण के लिए पहले देश में 4 कंपनियां ही थीं, आज 9 कंपनी इन मेडिसिंस को बना रही हैं। मोदी सरकार ब्लैक फंगस को भी ख़त्म करने के लिए कृतसंकल्पित है।

श्री नड्डा ने कहा कि कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कोविड एफेक्टेड बच्चों के लिए एक स्कीम लेकर आये हैं। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों के 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दी जायेगी तथा 23 वर्ष के होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही, ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, उच्च शिक्षा और आसान ऋण की भी व्यवस्था की जायेगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत इन बच्चों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सेवा ही संगठन 2.0 अभियान के तहत अब तक देश में लगभग 1,951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए हैं, जिला स्तर तक 4,000 से अधिक हेल्पलाइन सेंटर्स स्थापित किये गए हैं। इस अभियान के तहत देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अब तक लगभग एक करोड़ फेस मास्क का वितरण किया है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगभग 29 लाख फ़ूड पैकेट्स और लगभग 17 लाख राशन किट्स का वितरण किया। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी भी इस अभियान में पीछे नहीं है। अब तक दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने 3.85 लाख फेस मास्क, लगभग 1.70 लाख फ़ूड पैकेट्स और लगभग 3.68 लाख राशन किट्स का वितरण किया है। दिल्ली में पार्टी के लगभग 55 हजार कार्यकर्ता वैक्सीनेशन में सहयोग, राहत अभियान और कोविड जागरुकता अभियान में लगे हुए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से साधुवाद देता हूं।

उन्होंने कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है जहां सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए समाज ने भी पूरी तन्मयता के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुनिया में अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने संकट की इस घड़ी में राजनीति से हटकर जनता की सेवा को ही अपना मंत्र बनाया। भाजपा के सेवा यज्ञ का काम दुनिया में रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है। पूरी दुनिया भारतीय जनता पार्टी की सेवा के दर्शन की सराहना कर रही है। ■

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा की सहमति से 31 मई, 2021 को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दिकी ने मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। मोर्चा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी के लिए नए नामों की घोषणा की गई। विज्ञप्ति के अनुसार डॉ. अब्दुल सलाम, श्री मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी, श्री एस.एम. अकरम, श्री जाकिर हुसैन, श्री मो. हुसैन खान एवं श्री अजमल हुसैन जैदी अल्पसंख्यक मोर्चा के नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और श्री साबिर अली, सूफी एम.के. चिश्ती एवं श्री जोशुआ पीटर डिसूजा को नए राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया गया है। ■

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान 'सेवा ही संगठन 2.0' अभियान

'सेवा ही संगठन 2.0' अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता कोविड प्रभावित और अन्य जरूरतमंद लोगों को राशन किट, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, दवाएं आदि सहित राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता देश भर में बीमार लोगों को कोरोना परीक्षण कराने और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी मदद कर रहे हैं।

इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब तक देश भर में लगभग 1,951 रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं। सभी राज्यों में जिला स्तर पर लगभग 4,000 समर्पित कोविड हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश भर में लगभग 1 करोड़ फेस मास्क, 29 लाख खाने के पैकेट और लगभग 17 लाख राशन किट भी वितरित किए हैं।

अन्य राज्यों की तरह पंजाब, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ता भी जरूरतमंदों को भोजन, राशन, फेस गार्ड, स्टीमर और अन्य आवश्यक सामान वितरित कर रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। 'सेवा ही संगठन' कार्यक्रम के तहत ओडिशा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी यास चक्रवात के बाद प्रभावित जिलों के दौरान भोजन और आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इन कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा, "मैं अपने उन करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो देश भर में महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित और अथक प्रयास कर रहे हैं।"

आंध्र प्रदेश

जम्मू-कश्मीर

ओडिशा

पंजाब

नवंबर, 2021 तक 80 करोड़ लोगों को हर महीने मिलता रहेगा मुफ्त खाद्यान्न

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सात जून को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' (पीएमजीकेएवाई-3) को दीपावली तक बढ़ाने के फैसले के बारे में जानकारी दी। इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर, 2021 तक हर महीने निश्चित मात्रा में मुफ्त खाद्यान्न मिलता रहेगा।

गौरतलब है कि सात जून, 2021 तक भारतीय खाद्य निगम सभी 36 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को 69 एलएमटी मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर चुका है। 13 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा ने मई-जून, 2021 के लिए हुए आवंटन का पूरी तरह उठान कर लिया है।

23 राज्यों/यूटी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन दीव डीएंडएनएच, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने मई, 2021 के आवंटन का 100 प्रतिशत प्राप्त कर लिया है।

पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ने मई-जून, 2021 के आवंटन का पूरी तरह उठान कर लिया है। मणिपुर और असम में मुफ्त खाद्यान्न को प्राप्त करने का काम तेजी से जारी है और जल्द ही इसके पूरे होने की संभावना है।

एफसीआई सभी राज्यों/यूटी सरकारों को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्यान्न पहुंचा रहा है। मई, 2021 के दौरान एफसीआई द्वारा 46 रैक्स प्रतिदिन की दर से 1433 खाद्यान्न रैक्स का लदान किया गया।

भारत सरकार राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ किसी भी प्रकार की साझीदारी के बिना खाद्य सब्सिडी, अंतर-राज्यीय परिवहन और डीलर मार्जिन/अतिरिक्त डीलर मार्जिन का पूरी तरह वहन करेगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का ऐलान किया था। योजना के तहत एनएफएसए के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न दिया जा रहा है

भारत सरकार ने सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों को पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न का मुफ्त वितरण समयबद्ध तरीके से करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मौजूदा कोविड महामारी के बीच लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

भारत सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पैदा आर्थिक हालातों से गरीबों के सामने आई मुश्किलों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का ऐलान किया था। योजना के तहत एनएफएसए के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न दिया जा रहा है। ■

भारत को मिली 8 नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमियां

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की उदार उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) नीति के तहत भारत को 8 नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमियां मिलने वाली हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की दो जून को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ये अकादमियां बेलगावी, जलगांव, कलबुर्गी, खजुराहो और लीलाबाड़ी में स्थापित की जाएंगी।

इन 8 एफटीओ की स्थापना का उद्देश्य भारत को वैश्विक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र बनाना और विदेश में स्थित एफटीओ में भारतीय कैडेटों के पलायन को रोकना है। इसके अतिरिक्त, इन एफटीओ को भारत के पड़ोसी देशों में कैडेटों की उड़ान प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी डिजाइन किया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण टीम की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प इस बात से साबित होती है कि वह कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण खड़ी हुई चुनौती के बावजूद बोली प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सफल रही। इन पांच हवाई अड्डों का चयन बेहद सावधानीपूर्वक किया गया है। इन जगहों पर मौसम और नागरिक/सैन्य हवाई यातायात के कारण न्यूनतम व्यवधान रहता है। यह पहल भारतीय उड़ान प्रशिक्षण क्षेत्र को 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने नवंबर, 2020 में इसके लिए बोलियां आमंत्रित की थीं। 31 मई, 2021 को चयनित हुए बोलीदाताओं को अवार्ड लेटर जारी किए गए। इसके तहत एशिया-पैसिफिक, जेटसर्व, रेडबर्ड, सम्वर्धन और स्काईनेक्स का चयन हुआ। ■

आईआईएससी बंगलुरू अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर

क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष-200 स्थानों में तीन भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह बनायी है। आईआईएससी बंगलुरू अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में प्रथम स्थान पर है। क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंडस, वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों ने नौ जून को विश्व की अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण जारी किया।

इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 177वां स्थान, आईआईटी दिल्ली को 185वां स्थान और आईआईएससी बंगलुरू को 186वां स्थान प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 200 संस्थानों की सूची में शामिल होने के लिए आईआईटी बंबई, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलूरु को बधाई दी।

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि आईआईएससी बेंगलूरु, आईआईटी बंबई और आईआईटी दिल्ली को बधाई। भारत के अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा वैश्विक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने और युवाओं के बीच बौद्धिक

कौशल का समर्थन करने के लिए प्रयास जारी हैं।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि भारत शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा रहा है और एक विश्वगुरू के रूप में उभर रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी पहल हमारे कॉलेजों और संस्थानों को वैश्विक स्तर पर रैंकिंग दिलाने में सहायक साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्यूएस एवं टाइम्स ग्रुप द्वारा घोषित विश्वविद्यालय रैंकिंग को देखकर इस तथ्य को महसूस किया जा सकता है। ■

अब भारतीय रेल होगी और सुरक्षित

आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नौ जून को भारतीय रेल (आईआर) को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव व सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इस स्पेक्ट्रम के साथ ही भारतीय रेल ने अपने मार्ग पर एलटीई (लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन) आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान करने की परिकल्पना की है। परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी।

इसके अलावा, भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को मंजूरी दी है जो रेलगाड़ी को टक्कर से बचने में मदद करेगा और इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इससे रेलवे के परिचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था में रणनीतिक बदलाव आएगा। यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए लाइन क्षमता और सुरक्षा को बेहतर करने में मदद करेगा।

आधुनिक रेल नेटवर्क तैयार होने से परिवहन लागत में कमी आएगी और प्रवाह क्षमता में सुधार होगा। साथ ही, यह बहुराष्ट्रीय उद्योगों को अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आकर्षित करेगा जिससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को पूरा करने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को दी मंजूरी

भारतीय रेल के लिए एलटीई का उद्देश्य परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद वॉइस, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना है। इसका उपयोग आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाएगा तथा लोको पायलटों व गार्डों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित रिमोट ऐसेट मॉनिटरिंग विशेष रूप से कोच, वैगन व लोको की निगरानी और ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों की लाइव वीडियो फीड, ट्रेन के सुरक्षित एवं तेज संचालन को सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा।

इसके लिए ट्राई की सिफारिश के अनुसार निजी उपयोग पर रॉयल्टी शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जा सकता है। ■

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़कर 1,940 रुपये हुआ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने नौ जून को कृषि उपज की सरकारी खरीद, सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी।

केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 72 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,940 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। बीते साल की तुलना में सबसे ज्यादा तिल यानी सेसामम (452 रुपये प्रति क्विंटल) और उसके बाद तुअर व उड़द (300 रुपये प्रति क्विंटल) के एमएसपी में बढ़ोतरी की सिफारिश की गई।

मूंगफली और नाइजरसीड के मामले में बीते साल की तुलना में क्रमशः 275 रुपये और 235 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मूल्यों में इस अंतर का उद्देश्य फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन देना है।

कृषि उपज की सरकारी खरीद, सीजन 2021-22 के लिए सभी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार हैः

फसल	एमएसपी 2020-21	एमएसपी 2021-22	उत्पादन की लागत 2021-22 (रुपये/क्विंटल)	एमएसपी में बढ़ोतरी (पूर्ण)	लागत पर रिटर्न (प्रतिशत में)
धान (सामान्य)	1868	1940	1293	72	50
धान (ग्रेड ए)	1888	1960	-	72	-
ज्वार (हाइब्रिड) (हाइब्रिड)	2620	2738	1825	118	50
ज्वार (मलडंडी)	2640	2758	-	118	-
बाजरा	2150	2250	1213	100	85
रागी	3295	3377	2251	82	50
मक्का	1850	1870	1246	20	50
तुअर (अरहर)	6000	6300	3886	300	62
मूंग	7196	7275	4850	79	50
उड़द	6000	6300	3816	300	65
मूंगफली	5275	5550	3699	275	50
सूरजमुखी के बीज	5885	6015	4010	130	50
सोयाबीन (पीली)	3880	3950	2633	70	50
तिल	6855	7307	4871	452	50
नाइजरसीड	6695	6930	4620	235	50
कपास (मध्यम रेशा)	5515	5726	3817	211	50
कपास (लंबा रेशा)	5825	6025	-	200	-

सरकारी खरीद, सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी आम बजट 2018-19 में उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत (सीओपी) से कम से कम 1.5 गुने के स्तर पर एमएसपी के निर्धारण की घोषणा के क्रम में की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए तार्किक रूप से उचित लाभ सुनिश्चित करना है।

किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर सबसे ज्यादा अनुमानित रिटर्न बाजरा (85 प्रतिशत) पर, उसके बाद उड़द (65 प्रतिशत) और तुअर (62 प्रतिशत) पर होने की संभावना है। बाकी फसलों के लिए किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न होने का अनुमान है।

पिछले कुछ साल के दौरान तिलहनों, दालों और मोटे अनाज के पक्ष में एमएसपी में बदलाव की दिशा में हुए ठोस प्रयासों का उद्देश्य किसानों को अपने खेतों के ज्यादा हिस्से में इन फसलों को लगाने और सर्वश्रेष्ठ तकनीकों व कृषि विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे मांग-आपूर्ति में संतुलन कायम किया जा सके।

पोषण संपन्न पोषक अनाजों पर जोर ऐसे क्षेत्रों में इनके उत्पादन को प्रोत्साहन देना है, जहां भूजल पर दीर्घकालिक विपरीत प्रभावों के बिना धान-गेहूं पैदा नहीं किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, वर्ष 2018 में सरकार द्वारा घोषित अम्ब्रेला योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) से किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी रिटर्न में बढ़ोतरी होगी। अम्ब्रेला योजना में प्रायोगिक आधार पर तीन उप-योजनाएं- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य अंतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी खरीद व भंडारण योजना (पीपीएसएस)- शामिल हैं। ■

ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 27600 मीट्रिक टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की

भारतीय रेल सभी बाधाओं को पार करते हुए तथा नए समाधान निकाल कर देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) पहुंचाना जारी रखे हुए है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस देश की सेवा में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने में 27000 मीट्रिक टन को पार कर गई।

भारतीय रेल द्वारा आठ जून तक देश के विभिन्न राज्यों में 1603 से अधिक टैंकरों में लगभग 27600 मीट्रिक टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। ज्ञात हो कि 392 ऑक्सीजन एक्सप्रेस गाड़ियों ने अपनी यात्रा पूरी कर विभिन्न राज्यों को सहायता पहुंचाई है।

ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा तमिलनाडु में 3700 एमटी से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में क्रमशः 2700, 3000 और 3300 मीट्रिक टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है।

ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 45 दिन पहले 24 अप्रैल को महाराष्ट्र में 126 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की डिलीवरी करने के साथ अपना काम प्रारंभ किया था। भारतीय रेलवे का यह प्रयास रहा है कि ऑक्सीजन का अनुरोध करने वाले राज्यों को कम से कम संभव समय में अधिक से अधिक संभव ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके।

ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा 15 राज्यों- उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम को ऑक्सीजन सहायता पहुंचाई गई है।

आठ जून तक महाराष्ट्र में 614 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, उत्तर प्रदेश में लगभग 3797, मध्य प्रदेश में 656 मीट्रिक टन, दिल्ली में 5790 मीट्रिक टन, हरियाणा में 2212 मीट्रिक टन, राजस्थान में 98 मीट्रिक टन, कर्नाटक में 3341 मीट्रिक टन, उत्तराखंड में 320 मीट्रिक टन, तमिलनाडु में 3773 मीट्रिक टन, आंध्र प्रदेश में 3049 मीट्रिक टन, पंजाब में 225 मीट्रिक टन, केरल में 513 मीट्रिक टन, तेलंगाना में 2765 मीट्रिक टन, झारखंड में 38 मीट्रिक टन और असम में 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है।

भारतीय रेल ने ऑक्सीजन सप्लाई स्थानों के साथ विभिन्न मार्गों की मैपिंग की है और राज्यों की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुसार अपने को तैयार रखा है। भारतीय रेल को एलएमओ लाने के लिए टैंकर राज्य प्रदान करते हैं। ■

हमारे राष्ट्रवाद का आधार सांस्कृतिक है

दीनदयाल उपाध्याय

हम अपने इतिहास में राष्ट्र शब्द का प्रयोग या व्यवहार अनेक स्थानों पर पाते हैं। राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र विजयी हो— इसकी कामना वैदिक सूत्रों में की गई है, समृद्धि की भावना व्यक्त की गई है। स्वस्तिवाचन में भी राष्ट्र शब्द का व्यवहार होता है। अतः हम पहले राष्ट्र हैं, यह बात अच्छी प्रकार से समझ लें।

कुछ लोग कहते हैं कि भारत में पहले राष्ट्रीयता नाम की कोई वस्तु थी ही नहीं। अब राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज बनानी है। ऐसा कहनेवाले वे लोग हैं, जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा का अध्ययन किया है। आज की भाषा में जिन्हें राष्ट्र कहा जाता है, पश्चिमी देशों में आज से पांच सौ-सात सौ वर्ष या एक हजार वर्ष पूर्व कोई राष्ट्र नहीं था। वहां जितने भी लोग थे, जातियां थीं, मजहब के नाम पर बंटे हुए थे। ईसाई, यहूदी, मुसलमान आदि। प्राचीन यूनान में अवश्य राष्ट्रीयता का कुछ स्वरूप था, परंतु उनके समाप्त होने पर जो आए, वे सब मजहब के नाम पर थे। यहूदी, ईसाइयों की मुसलमानों की इस प्रकार उस समय यूरोप व एशिया में जो भी लड़ाइयां हुईं, मजहब के नाम पर हुईं, जिन्हें क्रूसेड्स कहते हैं। उनमें प्रत्येक मजहब के पक्ष के लोग दूर-दूर से आते

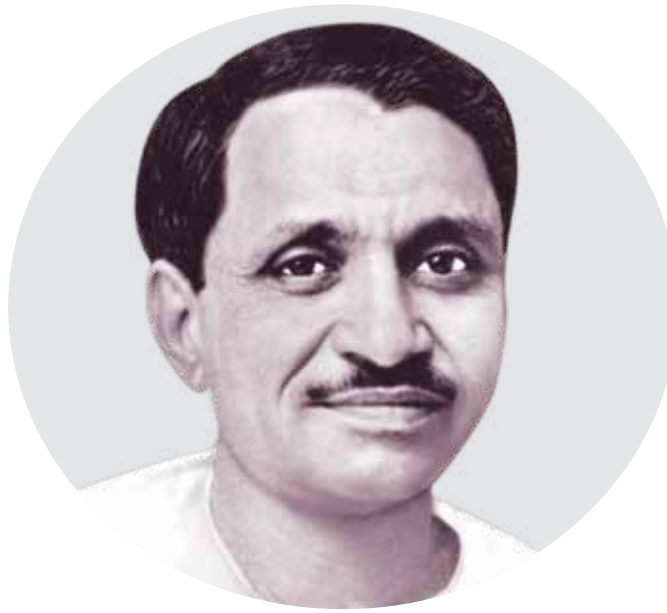

थे। कुछ समय तक सुधार के नाम पर नया मजहब आया प्रोटेस्टेंट। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटो की लड़ाइयां

हमारे यहां का राष्ट्रवाद कल्चरल (सांस्कृतिक) है। भूमि व राज्य इसके पोषक हैं। अन्य देशों में पहले राज्य, उसके लिए भूमि और उसकी पोषक संस्कृति है

हुईं। एक स्थिति ऐसी थी कि रोम का पोप संपूर्ण का ईसाई जगत का सम्राट माना जाता था। वही धार्मिक गुरु था तथा वही राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से सम्राट था।

मुसलमानों में भी सभी शक्ति का केंद्र खलीफा था, सभी मुसलमानी राज्य उसके नाम पर थे, वह सम्राट, शेष सभी राजा उसके प्रतिनिधि माने जाते थे। पर यह बात अधिक दिन तक नहीं चली, धीरे-धीरे स्थिति बदली। यूरोप में पोप के विरुद्ध लोग खड़े हो गए। जर्मनी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंट मजहब आया। उसने पोप की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। इंग्लैड में भी एक नया चर्च—एंगलीकन चर्च बना। धीरे-धीरे इंग्लैड, फ्रांस, जर्मनी से रोम का प्रभुत्व हट गया। अन्य देशों में भी ऐसा ही हुआ। वे भी उनके प्रभुत्व से मुक्त हो गए। धीरे-धीरे इनमें कुछ लोगों ने प्रयत्न किया और समूहों को जोड़कर राज्य निर्माण किए। सभी प्रकार के लोगों को जोड़कर राष्ट्र की स्थिति निर्माण हुई। इटली में मैजिनी और गैरीबाल्डी ने छोटे-छोटे राज्यों को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा ही जर्मनी में हुआ, ऐसा ही फ्रांस में हुआ। इंग्लैड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड भी मिलकर एक इकाई के रूप में बने। इस प्रकार राष्ट्रीयता बनी। इसी प्रकार उस शिक्षा को प्राप्त किए हुए लोग सोचते हैं कि भारत में भी पहले राष्ट्रीयता नहीं थी। जब अंग्रेजों से हमारा संपर्क आया तो राष्ट्रीयता की भावना आई कि उन

देशों के समान ही हमें भी राष्ट्र बनाना है।

हमारी राष्ट्रीयता की कल्पना और पश्चिम से आई राष्ट्रीयता की कल्पना में एक आधारभूत अंतर है। यह राष्ट्रीयता की कल्पना राजनीतिक आधार पर नहीं, सांस्कृतिक आधार पर है। हमारे राष्ट्रवाद का आधार सांस्कृतिक है। कुल तीन प्रकार के राष्ट्रवाद हैं। प्रादेशिक (Territorial), राजनीतिक (Political) और सांस्कृतिक (Cultural)। हमारे यहां का राष्ट्रवाद कल्चरल (सांस्कृतिक) है। भूमि व राज्य इसके पोषक हैं। अन्य देशों में पहले राज्य, उसके लिए भूमि और उसकी पोषक संस्कृति है।

राष्ट्रीयता के सांस्कृतिक आधार का हमें लाभ भी रहा। हमारे देश में कितने भी राजनीतिक उतार-चढ़ाव आए, उससे राष्ट्रवाद को कभी कोई धक्का नहीं लगा। अन्य देशों में, राजनीतिक सत्ता समाप्त होते ही, राष्ट्रीयता भी समाप्त हुई। पर हमारे यहां राजनीतिक सत्ता को गौण स्थान देने से, सत्ता जाने पर भी राष्ट्रीयता बनी रही व बनी हुई है। हमारे यहां राष्ट्रीयता सांस्कृतिक रही। यहां चाहे एक राज्य था चाहे अनेक, राष्ट्रीयता बनी रही।

पर जो लोग ऐसा कहते हैं कि भारत की एकता अंग्रेजों के समय में ही रही, इससे पूर्व कभी नहीं रही, ऐसा सोचना ही भूल है। एक तो हमारी इस ओर देखने की दृष्टि कभी राजनीतिक नहीं रही, फिर भी चंद्रगुप्त के समय में राजनीतिक एकता अंग्रेजों के समय से भी अधिक ही थी। फिर पृथु, रघु, दिलीप, मांधाता आदि चक्रवर्ती सम्राटों के समय में तो संपूर्ण पृथ्वी ही हमारे अंतर्गत थी। बाद में हो सकता है, हमारे यहां राजा होंगे, पर अनेक राजाओं के रहने पर भी देश की ओर देखने की हमारी दृष्टि क्या है? हमारे देश के एक राज्य वालों ने अपने इसी देश के दूसरे राज्यवालों को दूसरे देश का समझा है क्या? बल्कि सदा यह प्रयत्न रहा कि भारत को एक देश के रूप में देखें। कोई भी पुण्यकार्य करते समय, संकल्प करते समय, यह संपूर्ण भारत हमारे सामने आया है। 'जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे...' — इस प्रकार कहते हैं। सारे देश की एकता हमारे सामने आई है।

हमारे यहां राजनीतिक सत्ता को गौण स्थान देने से, सत्ता जाने पर भी राष्ट्रीयता बनी रही व बनी हुई है। हमारे यहां राष्ट्रीयता सांस्कृतिक रही। यहां चाहे एक राज्य था चाहे अनेक, राष्ट्रीयता बनी रही

हमारे देश की जितनी भी महान कल्पनाएं आई हैं, उनमें संपूर्ण देश की एकता ही प्रस्फुटित हुई है— तर्पण पितृ श्राद्ध गया में करें, मातृश्राद्ध करें, अस्थियां गंगा में प्रवाहित करें। इन सबके सामने भारत की एकता की कल्पना नहीं थी क्या? राष्ट्रीयता की कल्पना नहीं होती तो ऐसा विचार भी नहीं आता। चारों धाम की यात्रा करनेवालों ने संपूर्ण भारत की ही तो कल्पना की थी। यदि उनको यह कल्पना नहीं होती तो वे धाम भारत के बाहर विदेशों मे भी बना सकते हैं। पर भारत में ही और वे भी भारत के चारों कोनों में पुण्य धाम बनाए। यह राष्ट्रीयता की कल्पना के ही कारण है। शक्ति के बावन पीठ भी पूरे भारत में फैले हुए हैं, देश के बाहर नहीं।

प्रजापति की कन्या सती बिना बुलाए ही शिवजी से स्वीकृति लेकर अपने पिता के यज्ञ में आईं, पिता की ओर से पति शिवजी को आमंत्रित न किए जाने का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। सती ने यज्ञाग्नि में प्राणों की आहुति दे दी। यज्ञ भंग हो गया। शिवजी सती की लाश लेकर सारे भारत में घूमते रहे। भारत में सभी की यही आकांक्षा रहती है कि जीवन में एक बार सभी तीर्थों में जाऊं और मरने पर भी मेरे शरीर की अस्थियां तीर्थों में प्रवाहित की जाएं। शिवजी संपूर्ण भारत में घूमे। जहां-जहां गए, सती का एक-एक अंग गिरता गया, वहीं शक्ति का, देवी का एक पीठ बन गया। आसाम, कलकत्ता, मथुरा आदि संपूर्ण भारत में बावन पीठ हैं। ये भारत के कोने-कोने में हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन बावन पीठों की यात्रा आवश्यक है। वैष्णवों के भी सारे भारत में एक सौ छप्पन तीर्थ हैं। हमारे ज्योतिर्लिंग भी संपूर्ण भारत में हैं। जैनियों के, बौद्धों के सबके तीर्थ संपूर्ण भारत में फैले हैं। सभी संप्रदायों ने अपने तीर्थ संपूर्ण भारत में बनाए हैं। शंकराचार्य ने चारों कोनों में पीठ बनाए। इसी प्रकार रामायण, महाभारत में इन दोनों महाकाव्यों का साहित्य सारे भारत में फैला हुआ है। कृष्ण भी द्वारका से, पश्चिम से, प्राग्ज्योतिषपुर, पूर्व तक गए। इस प्रकार दोनों का चरित्र संपूर्ण देश पर छाया है। सब पर छाया है। हम इन दो आदर्शों से अनुप्राणित देश हैं।

क्रमशः

(संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, अजमेर; मई १८, १९६३)

महान शिक्षाविद, प्रखर देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी महान शिक्षाविद, चिन्तक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतवर्ष की जनता उन्हें एक प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में जानती है। देश के करोड़ों लोगों के मन में उनकी एक निरभिमानी, देशभक्त की छवि अंकित है। वे आज भी बुद्धजीवियों और मनीषियों के आदर्श हैं। वे अब भी लाखों भारतवासियों के मन में एक पथप्रदर्शक एवं प्रेरणापुंज के रूप में समाए हुए हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। उनके ज्ञान, प्रतिभा और स्पष्टवादिता के कारण उनके मित्र और शत्रु सभी उनका आदर करते थे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत ने स्वतंत्रता के शुरुआती चरण में ही एक महान सपूत खो दिया।

डॉ. मुकर्जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को एक प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष बंगाल के एक जाने-माने व्यक्ति थे। डॉ. मुकर्जी ने कलकत्ता से स्नातक डिग्री प्राप्त की। वे 1923 में सीनेट के सदस्य (फैलो) बन गये। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1924 में कलकता उच्च न्यायालय में एडवोकेट के रूप में नाम दर्ज कराया। बाद में वे सन 1926 में 'लिंकन्स इन' में अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए और 1927 में बैरिस्टर बन गए।

वे तैंतीस वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बने और सन 1938 तक इस पद पर आसीन रहे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार के रूप में बंगाल विधान परिषद् के सदस्य चुने गए, लेकिन उन्होंने अगले वर्ष इस पद से उस समय त्यागपत्र दे दिया, जब कांग्रेस ने विधानमंडल का बहिष्कार कर दिया था। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए।

पंडित नेहरू ने उन्हें अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया। डॉ. मुकर्जी ने लियाकत अली खान के साथ दिल्ली समझौते के मुद्दे पर 6 अप्रैल, 1950 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। श्री मुकर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरू गोलवलकर जी से परामर्श करने के बाद 21 अक्तूबर, 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की नींव रखी और वे इसके पहले अध्यक्ष बने। सन 1952 के चुनावों में भारतीय जनसंघ ने संसद की तीन सीटें जीतीं, जिनमें से एक सीट पर श्री मुकर्जी जीतकर आए थे। उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनायी, जिसमें 32 सदस्य लोकसभा तथा 10 सदस्य राज्यसभा से थे।

डॉ. मुकर्जी ने जोरदार नारा बुलंद किया कि - एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे

डॉ. मुकर्जी जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था, वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। डॉ. मुकर्जी ने जोरदार नारा बुलंद किया कि - एक देश में दो निशान, एक देश में दो

प्रधान, एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।

संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉ. मुकर्जी ने धारा-370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की थी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत से काटने की साजिश रची जा रही है। पंडित नेहरू ने डॉ. मुकर्जी पर ही संदेह व्यक्त कर दिया। कोई भी समझौता अथवा रास्ता दिखाई न देने पर डॉ. मुकर्जी ने बिना परमिट जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने का फैसला कर लिया। उनकी इस घोषणा में देश की अखंडता के लिए बलिदान देने की उमंग स्पष्ट झलकती थी।

9 मई, 1953 को प्रातः 6.30 बजे डॉ. मुकर्जी रेलगाड़ी से अपने चंद साथियों के साथ जम्मू के लिए रवाना हुए, परंतु जब वे अपने साथियों सहित जम्मू की सीमा रावी नदी के किनारे लखनपुर पहुंचे तो कश्मीर मिलिशिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 23 जून, 1953 को संदिग्ध परिस्थितियों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की मौत हो गई।

'कमल संदेश' भारत मां के इस महान सपूत व भारतीय जनसंघ के संस्थापक को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन जून को फोन पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति हैरिस ने प्रधानमंत्री को अपनी 'ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग रणनीति' के तहत भारत सहित अन्य देशों को कोविड-19 टीके बनाने की अमेरिका की योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

श्री मोदी ने अमेरिका के निर्णय तथा हाल के दिनों में अमेरिकी सरकार, कंपनियों तथा अमेरिका स्थित भारतीय प्रवासी समुदाय से भारत को प्राप्त सहायता के सभी रूपों और एकजुटता के लिए उपराष्ट्रपति हैरिस की सराहना की।

दोनों नेताओं ने वैक्सीन मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र सहित अमेरिका और भारत के बीच स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने के जारी प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी की क्षमता तथा महामारी के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव के समाधान में क्वाड वैक्सीन पहल को रेखांकित किया।

श्री मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति के सामान्य हो जाने के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति हैरिस का भारत में स्वागत करने की उम्मीद जताई। ■

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा का निधन

हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा मुख्य सचेतक श्री नरेंद्र बरागटा का 5 जून, 2021 को चंडीगढ़ में निधन हो गया। वह काफी समय से अस्वस्थ थे। वे 69 वर्ष के थे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने श्री बरागटा के निधन पर शोक व्यक्त किया।

अपने शोक संदेश में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जुब्बल कोटखाई से विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के मुख्य सचेतक एवं मेरे साथी नरेंद्र बरागटा जी के निधन का समाचार सुन अत्यंत आहत हूं। सरकार और पार्टी दोनों जगह हमने साथ काम किया। बरागटा जी का पूरा समय प्रदेश के विकास और संगठन को मज़बूती देने के लिए समर्पित था।

उन्होंने कहा कि जन-कल्याण के कार्यों व संगठन निर्माण में उनका योगदान अविश्वसनीय है। उनका जाना हिमाचल व भाजपा के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। दुःख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिजनों, शुभचिंतकों एवं समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उनके निधन को पार्टी और प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।

श्री नरेंद्र बरागटा का जन्म 15 सितंबर, 1952 को जुब्बल कोटखाई में हुआ था। श्री बरागटा 1998 में शिमला विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक बने और प्रदेश में भाजपा नेतृत्व की सरकार में बागवानी राज्य मंत्री बने। 2007 में वह दोबारा जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए और भाजपा सरकार में मंत्री बने। ■

पूरी दुनिया के लिए जाना चाहिए 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' का संदेश: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 जून को जी-7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में भाग लिया। 'बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर-हेल्थ' शीर्षक से युक्त यह सत्र कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक निजात और भविष्य की महामारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को मजबूत बनाने पर केंद्रित था।

सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में कोविड संक्रमण की हालिया लहर के दौरान जी-7 और अन्य अतिथि देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। उन्होंने महामारी से लड़ने की दिशा में सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के सभी स्तरों के प्रयासों के तालमेल के साथ भारत के 'समग्र समाज' के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

श्री मोदी ने संपर्क ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग के बारे में भी जानकारी दी और अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य शासन में सुधार हेतु किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कोविड संबंधित प्रौद्योगिकियों पर टीआरआईपीएस छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा डब्ल्यूटीओ में प्रस्तावित प्रस्ताव पर जी-7 का समर्थन मांगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज की बैठक से पूरी दुनिया के लिए 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' का संदेश जाना चाहिए। भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए श्री मोदी ने इस संबंध में लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों के विशेष दायित्वों पर बल दिया।

भारत की सभ्यता में रची-बसी है 'लोकतंत्र और स्वतंत्रता'

जी-7 शिखर वार्ता के 'आऊटरीच सेशंस' के दूसरे दिन 13 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो सत्रों में हिस्सा लिया।

भारतीय रेल विभाग ने तय किया है कि 2030 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाये

मुक्त समाज वाले सत्र में प्रमुख वक्ता के रूप में बोलने के लिये आमंत्रित प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि किस तरह लोकतंत्र और स्वतंत्रता, भारत की सभ्यता में रची-बसी है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने और उन्हें किसी भी तरह ठेस न पहुंचे, इसके लिये साइबर स्पेस को हमेशा एक मंच बना रहना चाहिये। अलोकतांत्रिक और असमान प्रकृति वाले वैश्विक शासन संस्थानों का उल्लेख करते हुये श्री मोदी ने याद दिलाया कि बहुस्तरीय प्रणाली में सुधार ही मुक्त समाजों के अस्तित्व को कायम रखने की गारंटी है।

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की अटल प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुये श्री मोदी ने बताया कि भारतीय रेल विभाग ने तय किया है कि 2030 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य पूरा कर लिया जाये। उन्होंने जोर दिया कि जी-20 देशों में केवल भारत ही पेरिस समझौते की प्रतिबद्धता पूरी कर रहा है।

श्री मोदी ने यह हवाला दिया कि भारत द्वारा शुरू की गई दो प्रमुख वैश्विक पहलें बहुत प्रभावशाली साबित हो रही हैं। इन दोनों पहलों में सीडीआरआई (कोएलीशन फॉर डिसास्टर रेज़ेलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर– आपदा अनुकूल संरचना गठबंधन) और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देशों की जलवायु वित्त तक अच्छी पहुंच हो। उन्होंने आह्वान किया कि जलवायु परिवर्तन पर आमूल सोच की जरूरत है, जिसमें समस्याओं को कम करना, लाभप्रद पहलों को अपनाना, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, जलवायु वित्तपोषण, समानता, जलवायु न्याय और जीवन शैली में परिवर्तन जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।

वैश्विक एकजुटता और एकता, खासतौर से मुक्त और लोकतांत्रिक समाजों व अर्थव्यवस्थाओं के लिये स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक बहाली की चुनौतियों से निपटने के लिये श्री मोदी के संदेश का शासनाध्यक्षों ने स्वागत किया। ■

विद्यार्थियों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्णः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जून को सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अधिकारियों ने अब तक हुए व्यापक परामर्श के साथ-साथ राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से प्राप्त विचारों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

कोविड के कारण उत्पन्न अनिश्चित परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त राय एवं सुझावों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। यह भी निर्णय लिया गया कि सीबीएसई 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के परिणामों को समयबद्ध तरीके से एक पूर्णतः स्पष्ट उद्देश्यपरक मानदंड के अनुसार संकलित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि सीबीएसई की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं पर फैसला विद्यार्थियों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 ने अकादमिक कैलेंडर को काफी प्रभावित किया है और बोर्ड परीक्षाओं का मुद्दा विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के बीच अत्यधिक चिंता उत्पन्न करता रहा है, जिसे अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि देशभर में कोविड से जुड़ी स्थिति निरंतर बदल रही है। वैसे तो कोविड के मामले घट रहे हैं और कुछ राज्य प्रभावकारी सूक्ष्म-कंटेनमेंट के माध्यम से महामारी

से निपट रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों ने अब भी लॉकडाउन का विकल्प चुना है। इस तरह की स्थिति में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति में विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि हमारे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अत्यधिक महत्व है और इस पहलू पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में इस तरह की परीक्षाएं हमारे युवाओं को जोखिम में डालने का कारण नहीं बन सकती हैं।

श्री मोदी ने कहा कि सभी हितधारकों को विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि परिणाम पूर्णतः स्पष्ट मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं।

श्री मोदी ने व्यापक परामर्श प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए इस बात की सराहना की कि भारत के कोने-कोने से सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद ही विद्यार्थी हितैषी निर्णय लिया गया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राय एवं सुझाव देने के लिए राज्यों का भी धन्यवाद किया।

यह भी निर्णय लिया गया कि पिछले साल की तरह ही यदि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं, तो स्थिति अनुकूल होने पर सीबीएसई द्वारा उन्हें ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इससे पहले 21 मई, 2021 को एक उच्चस्तरीय बैठक की थी जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके बाद 23 मई, 2021 को रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया था। बैठक में सीबीएसई की परीक्षाएं कराने के बारे में विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई थी और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से राय एवं सुझाव प्राप्त हुए थे।

बैठक में गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, सूचना एवं प्रसारण, पेट्रोलियम और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रियों और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव और स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभागों के सचिव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। ■

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान 'यास' से हुए नुकसान की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान 'यास' के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए 28 मई, 2021 को ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उन्होंने ओडिशा के भद्रक और बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर में चक्रवात से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया।

भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राहत और पुनर्वास संबंधी उपायों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्री मोदी को बताया गया कि चक्रवाती तूफान 'यास' के कारण सबसे अधिक नुकसान ओडिशा में हुआ है और पश्चिम बंगाल एवं झारखंड के कुछ हिस्से भी प्रभावित हुए हैं।

प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत संबंधी गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की। ओडिशा को 500 करोड़ रुपये तुरंत दिए जायेंगे। शेष 500 करोड़ रुपये की राशि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड को दिए जाने की घोषणा की गई, जो नुकसान के आधार पर जारी की जाएगी।

केन्द्र सरकार नुकसान का संपूर्ण आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी दल को प्रभावित राज्यों का दौरा करने के लिए तैनात करेगी। इस टीम के आकलन के आधार पर आगे की सहायता दी जाएगी।

पूरे भारत में चक्रवाती तूफान 'यास' के कारण मृत व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी

श्री मोदी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लोगों को आश्वस्त दिया कि केन्द्र सरकार इस कठिन घड़ी में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने चक्रवात से पीड़ित सभी लोगों के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की और इस आपदा के दौरान अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने इस चक्रवात के कारण मृत व्यक्ति के परिजन को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

श्री मोदी ने कहा कि हमें आपदाओं के व्यापक वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान देना जारी रखना होगा। जैसे-जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आवृत्ति और उसके प्रभाव बढ़ रहे हैं, हमारी संचार प्रणालियों, नियंत्रण के प्रयासों और तैयारियों को एक बड़े बदलाव से गुजरना होगा। उन्होंने राहत के प्रयासों में बेहतर सहयोग के लिए लोगों के बीच विश्वास बनाने के महत्व के बारे में भी बताया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ओडिशा सरकार की तैयारियों और आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों की सराहना की, जिसकी वजह से जानमाल का बहुत कम नुकसान हुआ है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि ओडिशा ने इस किस्म की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दीर्घकालिक स्तर के नियंत्रण संबंधी प्रयास शुरू किए हैं।

श्री मोदी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि वित्त आयोग ने भी 30,000 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान करके आपदा के प्रभाव को कम करने पर जोर दिया है। ■

खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र के केन्द्र में है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में मात्र 50 दिन बचे होने के अवसर पर भारत की ओलंपिक तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों द्वारा आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए परिचालन संबंधी तैयारी के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक प्रस्तुति दी गई।

समीक्षा के दौरान श्री मोदी को महामारी के बीच एथलीटों के लिए निर्बाध प्रशिक्षण सुनिश्चित करने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, एथलीटों के टीकाकरण और उन्हें प्रदान की जा रही विशिष्ट सहायता की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों से अवगत कराया गया।

वैश्विक स्तर पर सफलता पाने वाले प्रत्येक युवा खिलाड़ी को देखकर हजार और लोग खेलों में आने के लिये प्रेरित होंगे

अधिकारियों ने टीकाकरण की स्थिति और सहयोगी स्टाफ के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि टोक्यो ओलंपिक के लिए यात्रा करने वाले प्रत्येक योग्य/संभावित एथलीट, सहयोगी स्टाफ और अधिकारियों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सभी भारतवासियों की ओर से शुभकामनाएं देने के लिए वे जुलाई में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे ओलंपिक दल के साथ जुड़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि खेल हमारे राष्ट्रीय चरित्र के केंद्र में है और हमारे युवा खेल की एक मजबूत और जीवंत संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि 135 करोड़ भारतवासियों की शुभकामनाएं हमारे उन युवाओं के साथ हैं, जो इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर सफलता पाने वाले प्रत्येक युवा खिलाड़ी को देखकर हजार और लोग खेलों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रेरित करने और उनका मनोबल बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसलिए प्रतियोगिता के दौरान भारत में उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा।

श्री मोदी को बताया गया कि 11 खेल स्पर्धाओं में 100 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है और लगभग 25 और एथलीटों के टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की संभावना है, जिसका विवरण जून, 2021 के अंत तक सामने आएगा। जबकि कुल 19 भारतीय एथलीटों ने 2016 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पिछले पैरालिंपिक्स में भाग लिया था।

टोक्यो ओलंपिक के लिए 26 पैरा एथलीटों ने क्वालीफाई किया है तथा 16 और एथलीटों के क्वालीफाई करने की संभावना है। ■

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने की 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' की सराहना

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत की ओर से 11 जून को जारी एक स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) को 'स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक अत्यंत सफल मॉडल' के रूप में सराहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे कई अन्य देशों में भी इसे सर्वोत्तम प्रथा के रूप में अपनाया जाना चाहिए जहां कई कारणों से विकास में क्षेत्रीय असमानता मौजूद हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एडीपी के तहत किए गए ठोस प्रयासों के कारण पहले से उपेक्षित जिलों, जिनमें दूरदराज के जिले और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले शामिल हैं, में पिछले तीन वर्षों के दौरान पहले के मुकाबले कहीं अधिक विकास हुआ है। अपने सफर की कुछ बाधाओं के बावजूद एपीडी पिछड़े जिलों के बीच विकास को बढ़ावा देने में बेहद सफल रहा है।

यूएनडीपी इंडिया रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव शोको नोडा ने 11 जून को यह रिपोर्ट नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉ. राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत को सौंपी। इसमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है और सुधार के लिए सिफारिशें की गई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एडीपी के तहत किए गए ठोस प्रयासों के कारण पहले से उपेक्षित जिलों, जिनमें दूरदराज के जिले और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले शामिल हैं, में पिछले तीन वर्षों के दौरान पहले के मुकाबले कहीं अधिक विकास हुआ है।

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के मात्रात्मक विश्लेषण के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों के साक्षात्कार पर आधारित है जिसमें जिला कलेक्टर, केंद्रीय प्रभारी अधिकारी, जिला के सहायक अधिकारी एवं अन्य विकास भागीदार शामिल हैं।

यूएनडीपी का यह विश्लेषण एडीपी के 5 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित हैं जिनमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, बुनियादी ढांचा और कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन शामिल हैं। अध्ययन में पाया गया कि इस कार्यक्रम ने इन जिलों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है।

गैर-आकांक्षी जिलों के मुकाबले आकांक्षी जिलों का बेहतर प्रदर्शन

रिपोर्ट के अनुसार जहां स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा और कुछ हद तक कृषि एवं जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार दर्ज किया गया है, वहीं महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद अन्य संकेतक कहीं अधिक मजबूती की गुंजाइश को दर्शाते हैं। आकांक्षी जिलों और उनके समकक्षों के बीच तुलना पर पाया गया कि गैर-आकांक्षी जिलों के मुकाबले आकांक्षी जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

स्वास्थ्य एवं पोषण और वित्तीय समावेशन के क्षेत्रों में रिपोर्ट में पाया गया है कि घरों पर होने वाली डिलिवरी के

9.6 प्रतिशत अधिक मामलों में एक कुशल जन्म परिचारिका ने भाग लिया। गंभीर रक्ताल्पता वाली 5.8 प्रतिशत अधिक गर्भवती महिलाओं का इलाज किया गया, डायरिया से पीड़ित 4.8 प्रतिशत अधिक बच्चों का इलाज किया गया, 4.5 प्रतिशत अधिक गर्भवती महिलाओं ने अपनी पहली तिमाही में प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकरण करवाया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत क्रमशः 406 एवं 847 अधिक नामांकन हुए और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 1,580 अधिक खाते खोले गए।

यूएनडीपी ने बीजापुर और दंतेवाड़ा में 'मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान' की भी सराहना की है जिससे इन जिलों में मलेरिया के मामलों में क्रमशः 71 प्रतिशत और 54 प्रतिशत की कमी आई है। इसे आकांक्षी जिलों का एक 'सर्वोत्तम प्रथा' करार दिया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार जिलों ने यह भी स्वीकार किया है कि स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से उन्हें कहीं अधिक आसानी से कोविड संकट से निपटने में मदद मिली है। उदाहरण के लिए ओडिशा के मलकानगिरी जिले को ही लेते हैं जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के करीब स्थित है। लॉकडाउन के शुरुआती चरण के दौरान राज्य में वापस लौटने वाले कई प्रवासी श्रमिकों के लिए यह एक प्रवेश मार्ग बन गया था।

जिले के अधिकारियों ने दावा किया कि उन प्रवासियों को क्वारंटीन करने के लिए नए बुनियादी ढांचे का उपयोग संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों के रूप किया गया।

इस पहल की सफलता का श्रेय मुख्य तौर पर रियल-टाइम निगरानी के आंकड़े, सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को एक साथ करने और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के जबरदस्त लाभ को दिया गया है।

रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के तहत उद्देश्यों और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र एवं स्थानीय सरकारों, विकास भागीदारों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों को एकजुट करने की इसकी अनोखी सहयोगात्मक प्रकृति पर भी गौर किया गया है। यही वह प्रमुख स्तंभ है जिसने जिला आयुक्तों को 'एक मजबूत कोविड-19 प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और अपने संबंधित जिलों में पंचायतों, धार्मिक एवं समुदाय के नेताओं और विकास भागीदारों के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करते हुए इस वैश्विक महामारी की चुनौतियों से निपटने में समर्थ बनाया।

नरेन्द्र मोदी सहित शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने दिखाई उल्लेखनीय प्रतिबद्धता

रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व द्वारा दिखाई गई उल्लेखनीय प्रतिबद्धता को भी स्वीकार किया गया है। वर्ष 2018 में इस कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से ही प्रधानमंत्री ने लगातार जिला स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जिला कलेक्टरों को प्रेरित और उत्साहित किया है।

एडीपी के दृष्टिकोण के 3सी 'कन्वर्जेंस, कम्पिटिशन और कोलैबरेशन' यानी अभिसरण, प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि साक्षात्कार देने वाले अधिकतर लोगों ने अभिसरण के महत्व पर जोर दिया है जो कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिंक्रनाइज्ड नियोजन एवं शासन की दिशा में साथ मिलकर काम करने को बढ़ावा देता है।

इसी प्रकार, प्रतिस्पर्धा वाले पहलू को भी इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बेहतर निगरानी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में काफी मददगार पाया गया। इसने जिलों के लिए अपने प्रयासों को बेहतर करने और प्रगति पर नजर रखने के लिए एक प्रेरक के रूप में काम किया। इस कार्यक्रम ने जिलों की तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं को मजबूत किया है।

कुल मिलाकर रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के सकारात्मक प्रभाव की सराहना की गई है। साथ ही यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है कि विकास पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित किया जाए और अब तक प्राप्त विकास की गति को बनाए रखा जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मूल्यांकन के निष्कर्षों के आधार पर यह सिफारिश की जाती है कि इस कार्यक्रम की सफलता को बढ़ाया जाए और अन्य क्षेत्रों एवं जिलों भी उसे दोहराया जाए।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनवरी, 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने और सभी के लिए समावेशी विकास 'सबका साथ, सबका विकास' सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयास के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। ■

सौर ऊर्जा की क्षमता पिछले 6 वर्षों में लगभग 15 गुना बढ़ीः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पांच जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस समारोह को संबोधित किया। समारोह का आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। श्री मोदी ने समारोह के दौरान पुणे के एक किसान के साथ बातचीत भी की जिन्होंने जैविक खेती और कृषि में जैव-ईंधन के उपयोग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने "रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी ऑन रोडमैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025" जारी की। उन्होंने पुणे में इथेनॉल के उत्पादन और पूरे देश में वितरण के लिए महत्वाकांक्षी ई-100 पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। इस वर्ष के समारोह का विषय 'बेहतर पर्यावरण के लिए जैव-ईंधन को प्रोत्साहन' था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री प्रकाश जावडेकर, श्री पीयूष गोयल तथा श्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत रोडमैप जारी करके भारत ने एक और छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकता बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि इथेनॉल पर फोकस करने का बेहतर प्रभाव पयार्वरण के साथ-साथ किसानों के जीवन पर भी हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य प्राप्त करने का समय कम करके 2025 करने का संकल्प लिया है। इससे पहले इस लक्ष्य की प्राप्ति का समय 2030 तय किया गया था जिसे 5 वर्ष कम कर दिया गया है।

पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने के लक्ष्य की प्राप्ति का समय 2030 से घटाकर 2025 किया गया

इथेनॉल खरीद में आठ गुना वृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 2014 तक पेट्रोल में औसत रूप में केवल 1.5 प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाता था जो अब बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गया है। 2013-14 में देश में लगभग 38 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद हुई थी जो अब बढ़कर 320 करोड़ लीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल खरीद में आठ गुना वृद्धि से देश के गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ हुआ है।

श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच और 21वीं सदी की आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। सरकार इसी सोच के साथ लगातार हर क्षेत्र में नीतिगत फैसले ले रही है।

उन्होंने कहा कि आज देश में इथेनॉल के उत्पादन और खरीद के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। इथेनॉल तैयार करने वाली अधिकतर इकाइयां उन 4-5 राज्यों में केंद्रित हैं जहां गन्ने का अधिक उत्पादन होता है लेकिन अब खाद्यान्न आधारित डिस्टिलरी स्थापित की जा रही हैं ताकि पूरे देश में इसका विस्तार हो। देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि कृषि अपशिष्ट से इथेनॉल बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई चुनौतियों के प्रति जागरूक है और सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनाए गए सख्त और नरम रवैये की चर्चा की। उन्होंने सख्त रवैये के बारे में कहा कि अक्षय ऊर्जा के लिए हमारी क्षमता में पिछले 6-7 वर्षों में 250 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में हैं। विशेषकर सौर ऊर्जा की क्षमता पिछले 6 वर्षों में लगभग 15 गुना बढ़ी है।

श्री मोदी ने कहा कि देश ने नरम रवैये के साथ ऐतिहासक कदम उठाए हैं। आज देश का सामान्य जन सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने, बीच की सफाई और स्वच्छ भारत जैसे पर्यावरण समर्थक अभियानों में शामिल हुआ है और नेतृत्व कर रहा है। ■

पिछले सात वर्षों में देश ने राष्ट्रीय गौरव के कई क्षणों का किया अनुभव: नरेन्द्र मोदी

गत सात वर्षों में ही देश के अनेक पुराने विवाद पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं और इनकी वजह से पूर्वोतर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है

केंद्र सरकार की सातवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा किया कि इस दौरान देश ने कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण महसूस किए।

आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 77वीं कड़ी में देशवासियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात सालों में भारत ने किसी के दबाव में आए बगैर अपने संकल्पों से कदम उठाया और देश के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हां, हम सही रास्ते पर हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इन सात वर्षों में देश 'सबका-साथ, सबका-विकास, सबका-विश्वास' के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। उन्होंने कहा कि इन सात वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है, वह देश और देशवासियों की रही है।

पिछले सात सालों में बिजली, पानी, सड़क के अलावा बैंक खाते खोलने और आवास सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इन सात सालों में लोगों की करोड़ों खुशियों में शामिल होने का मौका मिला।

'आयुष्मान भारत' योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब कोई गरीब मुफ्त इलाज से स्वस्थ होकर घर आता है तो उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। उसे भरोसा होता है कि देश उसके साथ है। ऐसे कितने ही परिवारों के आशीर्वचन, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद लेकर हमारा देश मजबूती के साथ विकास की ओर अग्रसर है।

श्री मोदी ने कहा कि इन्हीं सात सालों में भारत ने डिजिटल लेनदेन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है और आज किसी भी जगह आसानी से चुटकियों में पैसे भेजे जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि गत सात वर्षों में ही देश के अनेक पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं और इनकी वजह से पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है।

उन्होंने कहा कि ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन सात सालों में इसीलिए संभव हुआ, क्योंकि इस दौरान हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया।

कोरोना महामारी से देश की लड़ाई का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन सात सालों में देश ने जहां कई सफलताएं हासिल की, वहीं उसे कई कठिन परीक्षाओं के दौर से भी गुजरना पड़ा लेकिन इन सबके बावजूद देश मजबूत होकर निकला है।

उन्होंने कहा कि यह तो एक ऐसा संकट है, जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है। बड़े-बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। इस वैश्विक-महामारी के बीच भारत, 'सेवा और सहयोग' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

ज्ञात हो कि 23 मई, 2019 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। भाजपा ने 303 सीटें जीतकर जनादेश हासिल किया और श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 मई को लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ■

201 सीएनजी संयंत्र राष्ट्र को समर्पित

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 8 जून को देश में गेल समूह के 201 सीएनजी स्टेशनों को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री प्रधान ने झांसी में पीएनजी आपूर्ति व्यवस्था का उद्घाटन किया तथा रायगढ़ मे वाहनों में ईंधन भरने के लिए मोबाइल ईंधन भराई इकाइयों (एमआरयू) का भी उद्घाटन किया।

इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि अब सरकार के प्रयासों से मेट्रो शहरों से जुड़ रहे सीएनजी स्टेशन और पाइप से प्राकृतिक गैस की सप्लाई देशभर के नगरों तथा शहरों में पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जलवायु परिवर्तन शमन ने लिए संकल्पबद्ध हैं और उनके प्रयासों ने विश्व को नेतृत्व दिया है और विश्व में भारत का कद बढ़ा है।

श्री प्रधान ने कहा कि भारत ने अधिक स्थाई ऊर्जा उपयोग के लिए 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस का 15 प्रतिशत भाग हासिल करने का संकल्प व्यक्त किया है जो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने, सीओपी-21 के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पूरी करने में सहायता देगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी और परिणामस्वरूप आयात बिल और आयात निर्भरता कम होगी।

श्री प्रधान ने कहा कि उनका मंत्रालय हाइड्रोजन, सीबीजी, ऐथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) तथा एलएनजी सहित स्वच्छ और हरित ईंधन को अधिक से अधिक अपनाने के लिए और उपयोग करने के लिए बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि आईओसीएल शीघ्र ही अपनी रिफाइनरी और वडोदरा में हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन प्रारंभ करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने देशभर में ऐथेनोल उत्पादन और वितरण के लिए ई-100 पायलट परियोजना शुरू की है और 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत ऐथेनोल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

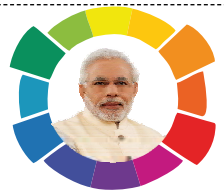

BECOME PART OF A VIBRANT IDEOLOGICAL MOVEMENT
BECOME PROUD MEMBER OF 'KAMAL SANDESH'

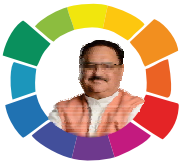

SUBSCRIPTION DETAILS

Name : .....

Address : .....

..... Pin : .....

Phone : ..... Mobile : (1)..... (2).....

E-mail : .....

SUBSCRIPTION TYPE						
	One Year	₹350/-	☐	Life Time (English or Hindi)	₹3000/-	☐
	Three Years	₹1000/-	☐	Life Time (English+Hindi)	₹5000/-	☐

(DETAIL OF THE PAYMENT)

Cheque/Draft No. :..... Date :..... Bank : .....

Note : * DD/Cheque will be made in favour of "**Kamal Sandesh**"
* Money order and Cash accepted with details

(Subscriber's Signature)

KAMAL SANDESH

SEND YOUR DD/CHEQUE ON THIS ADDRESS
Dr. Mookerji Smruti Nyas, PP-66, Subramania Bharati Marg, New Delhi-110003
Ph.: 011-23381428 **Fax:** 011-23387887 **E-mail:** kamalsandesh@yahoo.co.in

KAMAL SANDESH - DEDICATED TO NATIONAL CAUSE

चक्रवात यास से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वेसक वैश्विक समारोह को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 12वीं कक्षा के छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) सोसायटी की बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

आवरण: अजय कुमार सिंह